IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष के प्रति भारत के दृष्टिकोणः एक कूटनीतिक और रणनीतिक अध्ययन

डॉ0 सतीश कुमार

प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग, मेरठ कॉलेज, मेरठ

प्रीती गौड़

रिसर्च स्कॉलर, राजनीति विज्ञान, मेरठ कॉलेज, मेरठ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ (उ0प्र0)

प्रस्तावना

इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष आधुनिक इतिहास के सबसे जटिल और लंबे संघर्षों में से एक है जिसकी जड़े धार्मिक ऐतिहासिक और भू–राजनीतिक कारकों में समाहित है दुनिया के लगभग सभी राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार कभी इजराइल का तो कभी फिलिस्तीन का समर्थन करते है भारत भी अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार आजादी के बाद शुरुआती दौर में इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर एकतरफा फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा और इजराइल के साथ अपने संबंधों रणनीतिक तौर पर सीमित रखा। भारत ने 1947 के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 'फिलिस्तीन के क्षेत्रों में इजराइल के निर्माण' के खिलाफ मतदान किया और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाले गैर मुस्लिम राष्ट्रों में से एक था इस समर्थन के पीछे मुख्य कारण महात्मा गांधी के विचार, उपनिवेशवादी विचारधारा, धर्मनिरपेक्षता, भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक के प्रति संवेदनशीलता, राष्ट्रीय सुरक्षा, अरब देशों पर ऊर्जा आपूर्ति निर्भरता और गुटनिरपेक्ष देशों के साथ लगाव थे लेकिन 1990 के बाद भारत की बदलती राष्ट्रीय हित ने इजराइल के साथ विशेषकर रक्षा, प्रौद्योगिकी और कृषि के क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया। तब से लेकर लगातार भारत और इजराइल के मध्य संबंधों में काफी उतार चढ़ाव के बावजूद द्विपक्षीय संबंध मजबूत हुए इसका तात्पर्य यह नहीं है की फिलिस्तीन के साथ रिश्ते हाशिए पर चले गए भारत ने द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते हुए फिलिस्तीनी नेतृत्व के साथ कूटनीतिक संबंध जारी रखा है। उपर्युक्त संक्षिप्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो गई कि भारत जोकि 1990 से पहले फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण रखता था अब वह इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ अपने संबंधों को बनाए रखते हुए संतुलनकारी विदेश–नीति को अपना रहा है लेकिन 2014 के बाद भारत अपने सामरिक हितों को बढ़ावा देने के लिए डि हाइफनैशन और बहू–संरेखण जैसे नीतियों का प्रयोग कर इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य संतुलन बनाने के बजाय दोनों देशों के साथ अलग–अलग संबंधों को विकसित करना जैसे– 27 अक्तूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों को भारत फिलिस्तीन का हवाला दिए बिना इसे आतंकवादी हमला बताकर उसकी कड़ी निंदा की और इजराइल के प्रति सहानुभूति जताते हुए कहा की भारत किसी भी देश पर होने वाले आतंकवादी हमलों का समर्थन नहीं करता और वह इस दुखद घड़ी में इजराइल के साथ खड़ा है यह समर्थन स्पष्ट करता है कि अब भारत फिलिस्तीन मुद्दे को अपने राष्ट्रीय हितों पर हावी नहीं होने देगा।

इस शोध का मुख्य उद्देश्य इजराइल और फिलिस्तीन संघर्षों के प्रति भारत के प्रारंभिक और वर्तमान दृष्टिकोण अर्थात 2014 के बाद में क्या अंतर है तथा वर्तमान भारत अपने राष्ट्रीय हित को किस दिशा में आगे बढ़ा रहा है

मुख्य शब्द – राष्ट्रीय हित, हमास, इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष, आतंकवाद,

परिचय – इजराइल और फिलिस्तीन संघर्षों का इतिहास सदियों पुराना है जिस क्षेत्र पर वर्तमान इजराइल और फिलिस्तीन बसा हुआ है वह क्षेत्र कई सदियों से संघर्षों से घिरा हुआ है यह क्षेत्र विशेषकर येरूशलम तीन धर्मों 'इस्लाम, यहूदी और ईसाई' का पवित्र धर्मस्थल है जिस पर ऐतिहासिक दृष्टि से सबसे नवीनतम साम्राज्य 'आटोमन साम्राज्य' का कब्जा था जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन द्वारा जीत लिया गया था यह क्षेत्र तत्कालीन विवादों में उस समय आया जब ब्रिटेन 1917 में बाल्फोर घोषणा के माध्यम से यहूदी धर्म के लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक नए देश की स्थापना की घोषणा कर दी और धीरे–धीरे करके यहूदियों को बसाना शुरू कर दिया 1920 और 1930 के दशक में हिटलर के द्वारा लाखों यहूदियों का नरसंहार किया जिसकी वजह फिलिस्तीन में यहूदियों का निरंतर आप्रवासन बढ़ना और इस जगह को अपने राष्ट्र भूमि के रूप देखना इससे वहाँ बसे स्थानीय लोगों को अपने जमीन खोने व अल्पसंख्यक हो जाने का डर सताने लगा यहीं से वर्तमान इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष की शुरुआत हुई यह संघर्ष शुरुआत से ही विश्व के विभिन्न देशों को अपने पक्ष और विपक्ष में करते रहे भारत भी इससे अछूता नहीं रहा एक तरफ इजराइल का समर्थन करने वाले देश अमेरिका ब्रिटेन सहित पश्चिमी देश तो दूसरी तरफ फिलिस्तीन का समर्थन करने वाले अरब देश सहित अफगानिस्तान, भारत, पाकिस्तान, म्यांमार, इथोयोपिया आदि।

इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए संघर्ष के प्रति भारत के दृष्टिकोण–

फिलिस्तीन के प्रति आजादी से पहले भारतीय नेताओं का दृष्टिकोण – इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर भारत आजादी से पहले और बाद में लगभग 1990 तक फिलिस्तीन समर्थक रहा सन 1936 में यहूदी आप्रवासन और भूमि अधिग्रहण के खिलाफ अरब देशों ने विद्रोह शुरू कर दिया जिसे ब्रिटिश सरकार ने बलपूर्वक दबा दिया और इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा पील आयोग का गठन किया गया इस आयोग ने फिलिस्तीन में शांति स्थापना हेतु द्वि–राष्ट्र सिद्धांत का सुझाव दिया जिसका भारत विरोध करते हुए एक अखंड फिलिस्तीन राष्ट्र का समर्थन किया भारतीय नेताओं ने अरब संघर्ष और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में समानता देखी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश विस्तारवादी नीति 'साम्राज्यवाद' का विरोध करना 1938 में महात्मा गांधी फिलिस्तिनियों का पक्ष लेते हुए कहा कि "ठीक उसी तरीके से फिलिस्तीन अरबों का है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजों और फ्रांस फरांसीसियों का" गांधी जी का मानना था कि यहूदियों के उत्पीड़न का समाधान फिलिस्तीन में बसे अरब आबादी को विस्थापित करके नहीं होनी चाहिए बल्कि अरब देशों के साथ शांतिपूर्ण वार्ता करके यहूदियों के लिए मातृ भूमि की तलाश करनी चाहिए इसी तरीके से जवाहर लाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ नेता फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखते थे भारत द्वारा अरब देशों का समर्थन व जयोनिवाद का विरोध किए जाने के पीछे मुख्य कारण साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद विरोधी दृष्टिकोण, खिलाफत आंदोलन का प्रभाव, स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिम समुदाय के साथ की आवश्यकता, हिन्दू मुस्लिम एकता को लेकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को रोकना जिससे भारत का विभाजन धर्म के आधार पर ना हो, इसलिए फिलिस्तीन को धार्मिक पहचान के आधार पर विभाजित करने का विरोध करते हुए पंथ–निरपेक्ष सिद्धांत का समर्थन करना, गुट–निरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करना, शामिल है।

स्वतंत्रता से पहले फिलिस्तीन के लिए भारत का समर्थन ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरोध, अरब और मुस्लिम दुनिया के साथ एकजुटता और न्याय और आत्म–निर्णय के प्रति प्रतिबद्धता के संयोजन से प्रेरित था। भारतीय नेतृत्व ने अपने स्वयं के स्वतंत्रता संघर्ष पर ध्यान केंद्रित करते हुए, फिलिस्तीनी मुद्दे को उपनिवेशवाद और विदेशी शक्तियों द्वारा स्वदेशी आबादी के शोषण के खिलाफ बड़ी लड़ाई के हिस्से के रूप में देखा। इसके अतिरिक्त, फिलिस्तीन का समर्थन भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई में हिंदू–मुस्लिम एकता को बनाए रखने और भारत को वैश्विक स्तर पर अन्य उपनिवेश–विरोधी आंदोलनों के साथ जोड़ने का एक तरीका था।

1947 से 1990 तक इजराइल और फिलिस्तीन संघर्षों के प्रति भारत के दृष्टिकोण दृ

फिलिस्तीन के प्रति संवेदनशील विचारधारा का जन्म अंग्रेजी उपनिवेशवाद के खिलाफ भारतीय मुसलमानों का समर्थन हासिल करने के साथ हुआ प्रथम विश्व युद्ध में आटोमन साम्राज्य के विघटन के बाद सेव्रेस की संधि (इस संधि के माध्यम से ऑटोमन साम्राज्य से कई क्षेत्र छीन कर उसे राजनीतिक रूप से कमजोर करना) और खलीफा सुल्तान का अपमान किया जाना जिसके फलस्वरूप भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटिश शासन के खिलाफ खिलाफत आंदोलन चलाया गया गांधी जी ब्रिटिश शासन के फुट डालो और राज करो की नीति को कमजोर करने, हिन्दू मुस्लिम एकता को बढ़ावा और असहयोग आंदोलन में भारतीय मुस्लिम का साथ हासिल करने के लिए खिलाफत आंदोलन को एक अवसर के रूप में देखा, गांधी जी के अनुसार यदि हम लोग इस आंदोलन में मुसलमानों का साथ दिए तो मुस्लिम आबादी को एकजुट करने और ब्रिटिश उपनिवेशवाद को भारत से बाहर निकालने में सफलता हासिल की जा सकती है उस दौरान यह मकसद कामयाब तो हो गया लेकिन भारतीय

बुद्धिजीवियों ने हिंदुस्तान के दो भाग होने से रोक नहीं पाए। भारत आजादी के बाद से लगभग 1990 तक फिलिस्तीन को उसके हर मुद्दे पर समर्थन दिया हालांकि इजराइल के साथ भी आंशिक संबंध बनाए रखा।

संयुक्त राष्ट्र संघ संकल्प 181 (29 नवंबर 1947) – इजराइल फिलिस्तीन समस्या के समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में 'संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विभाजन प्रस्ताव (181) लाया गया जिसका उद्देश्य फिलिस्तीन को दो राज्यों में विभाजित करके येरूशलम शहर का अंतर्राष्ट्रीयकरण करना। इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान करते हुए भारत ने एकीकृत स्वतंत्र फिलिस्तीन राज्य और उसके आत्म–निर्णय के अधिकार का समर्थन किया जहां पर दोनों धर्म के लोग शांतिपूर्वक निवास कर सके क्योंकि भारत धार्मिक आधार पर विभाजन की त्रासदी को देख चुका था हालांकि 1950 में भारत इजराइल को राज्य के रूप में मान्यता दे दिया लेकिन राजनयिक संबद्ध को स्थापित नहीं किया।

प्रथम अरब इजराइल युद्ध (स्वतंत्रता युद्ध/नकबा) 1948 – फिलिस्तीन विभाजन के बाद इजराइल द्वारा अपने आप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देते ही अरब देश इजराइल पर हमला कर देते है जिसके परिणामस्वरूप इजराइल संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना की सीमाओं से परे जाकर अपने क्षेत्र का विस्तार कर लिया। भारत फिलिस्तीन विभाजन का विरोध करते हुए फिलिस्तीनी आत्मनिर्णय का समर्थन किया और इस संघर्ष को लेकर गैर–हस्तक्षेपवादी नीति अपनाई और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किए जा रहे शांतिपूर्ण समाधान के प्रयासों का समर्थन किया।

स्वेज नहर संकट (1956) – मिस्श्र द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किए जाने के बाद मिश्र पर इजराइल, ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा हमला कर दिया गया इस हमले का प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा कड़ी आलोचना की गई और इसे किसी संप्रभु राष्ट्र के खिलाफ साम्राज्यवादी कार्यवाई बताया भारत इस संघर्ष को समाप्त कराने हेतु मिश्र से विदेशी सैनिक वापस बुलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ में समर्थन जुटाने का प्रयास किया क्योंकि भारत उपनिवेशवाद विरोधी व अरब राष्ट्रवाद का समर्थक था।

छह दिवसीय युद्ध (1967) – अरब देश (मिश्र, सीरिया, जॉर्डन) और इजराइल के बीच हुए छह दिवसीय युद्ध में इजराइल की जीत हुई इजराइल ने मिश्र के गाजा पट्टी व सिनाई प्रायद्वीप, जॉर्डन के पश्चिमी तट व पूर्वी येरूशलम और सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया भारत इजराइल द्वारा किए गए आक्रमण व अवैध कब्जे का विरोध किया और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पारित प्रस्ताव 242 को लागू करने का समर्थन किया जिसमें यह शामिल था कि इजराइल कब्जे वाले क्षेत्र को उसके मूल देश को वापस लौटा दे भारत एक व्यापक सुधार के तहत इजराइली सेना की वापसी और फिलिस्तिनी राज्य के अधिकार के मान्यता का विचार रखा। इसी तरह 1973 के योम किप्पुर युद्ध और 1982 के लेबनान युद्ध में भारत अरब देशों का ही समर्थन किया।

1990 से पहले इजराइल–फिलिस्तीन संघर्ष में फिलिस्तीन को समर्थन देने के पीछे कारण– भारत द्वारा फिलिस्तीन को समर्थन देने के पीछे बाह्य व आंतरिक दोनों कारण मौजूद है

आंतरिक कारण –

1. **नैतिक कारण** – नैतिक–वादी विचारक महात्मा गांधी भारत में हिन्दू–मुस्लिम एकता को बनाए रखने व किसी राष्ट्र को धर्म के आधार पर विभाजित करने वाले सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए फिलिस्तीन पर यहूदी राज्य की स्थापना का विरोध किया यह विचार कई दशकों तक भारतीय प्रधानमंत्रियों को प्रभावित किया भारत फिलिस्तिनी संघर्ष को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समान माना जिसका मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्यवाद व उपनिवेश–वाद का विरोध करके देश को आजाद कराना।
2. **राजनीतिक कारण** – भारतीय मुस्लिम अल्पसंख्यक जोकि फिलिस्तीन के प्रति सहानुभूति रखता है ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल किसी मुस्लिम राष्ट्र का विरोध करके अपने वोट बैंक को प्रभावित नहीं कर सकती है पहली सबसे बड़ी धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक पार्टी कांग्रेस जो लंबे समय तक सत्ता में रही उसका झुकाव शुरुआत से ही फिलिस्तीन के प्रति रहा कांग्रेस विभाजन के बाद सांप्रदायिक संबंधों को लेकर संवेदनशील रहा वहीं दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भाजपा जिसका झुकाव इजराइल के तरफ देखा जाता है भाजपा फिलिस्तीन के साथ वैचारिक एकजुटता पर रणनीतिक और रक्षा सहयोग को प्राथमिकता देता है साथ ही इस्लाम–वादी चरम–पंथ व आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे इजराइल को रोल मॉडल के रूप में देखता है।
3. **घरेलू एकता को संतुलित करना** – आजादी के बाद भारत अपनी पहचान धर्म–निरपेक्ष देश के रूप में बनाया क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के संप्रदाय, जाति और धर्म के लोग निवास करते है सरकार आंतरिक अशांति से बचने के लिए (मुस्लिम समुदाय जिसका धार्मिक व भावनात्मक जुड़ाव अरब देशों के साथ था) फिलिस्तीन का समर्थन करना उचित समझा। जवाहर लाल नेहरू भारत को एक धर्मनिरपेक्ष

बहूलवादी राज्य के रुप देखते हुए सभी संप्रदाय में एकता बनाए रखने के प्रति संवेदनशील थे जिससे विश्व भर में भारत की छवि उपनिवेशवादी विरोधी, मानवाधिकार के प्रति सहानुभूति और देशों के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करने वाले के रूप में उभरे।

बाह्य कारण –

1. **साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध** – भारत की विदेशनीति साम्राज्यवाद विरोधी है क्योंकि भारत ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता के अधीन रहने वाले देशों में से एक है इसलिए जवाहर लाल नेहरू प्रत्येक उपनिवेशवाद से पीड़ित देशों के प्रति सहानुभूति रखते थे फिलिस्तीन में यहूदी समुदाय को बसाकर एक राष्ट्र के रूप इजराइल का निर्माण करना जो पश्चिमी शक्तियों द्वारा समर्थित एक औपनिवेशिक परियोजना है, का विरोध किया प्रधानमंत्री नेहरू 1947 में फिलिस्तीन विभाजन को भारतीय विभाजन के समान माना जिसके कारण लाखों नागरिकों की हत्या और विस्थापन हुआ ऐसे में प्रधानमंत्री फिलिस्तीन विभाजन के प्रति संवेदनशील थे।
2. **गुट–निरपेक्ष नीति** – भारत शीतयुद्ध के दौरान गुट–निरपेक्षता की नीति का पालन किया साम्राज्यवाद का विरोध और **आत्म–निर्णय के अधिकार** का समर्थन करना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्यों में से एक था भारत स्वयं को तत्कालीन आजाद हुए विकासशील देशों के नेता के रूप में देखा इसलिए वह किसी भी देश के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठाता रहा भारतीय प्रधानमंत्री फिलिस्तीन समस्या को औपनिवेशिक समस्या मानकर उसका समर्थन किया और इजराइल को पश्चिमी शक्तियों की चाल मानकर उसका विरोध किया हालांकि भारत गुटनिरपेक्ष रहते हुए भी रूस की तरफ झुका रहा इसके पीछे मुख्य कारण भारत के फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण का रूस द्वारा समर्थन किया जाना खासकर तब जब इजराइल को अमेरिका व पश्चिमी देशों का समर्थन हासिल हो
3. **ऊर्जा सुरक्षा** – स्वतंत्रता के बाद भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सुरक्षा की आपूर्ति अरब देशों पर निर्भर हो गई ऐसे परिस्थिति में भारत फिलिस्तीन का समर्थन करके अरब देशों के साथ आर्थिक व कूटनीतिक संबंध मजबूत किए। इस समर्थन का प्रभाव 1973 में आए तेल संकट के समय देखा जा सकता है जब अरब देशों द्वारा लगाए गए तेल प्रतिबंधों से भारत उबरने में सक्षम रहा।
4. **कश्मीर मुद्दा** – भारत के दुश्मन पड़ोसी देश पाकिस्तान के साथ अरब देशों का संबंध मजबूत होने के साथ–साथ वह ओ.आई.सी. (इस्लामिक सहयोग संगठन) का सदस्य था जिसकी वजह से वह बार–बार कश्मीर मुद्दे पर अरब देशों का समर्थन हासिल करना चाहा लेकिन भारत द्वारा फिलिस्तीन को दिए गए समर्थन की वजह से कई अरब देश कश्मीर मुद्दे पर अपनी तटस्थ रुख बनाए रखा। भारत के लिए गुटनिरपेक्ष और संयुक्त राष्ट्र संघ दोनों महत्वपूर्ण थे इन दोनों संगठन के अधिकांश देश विशेषकर अरब देश फिलिस्तीन के पक्षधर थे ऐसे परिस्थिति में कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान को अलग–थलग करने के लिए भारत फिलिस्तीन का समर्थन किया।

1947 से लेकर 1990 तक इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख फिलिस्तीन समर्थक रहा और इजराइल के साथ कूटनीतिक दूरी बनाए रखा भारत की विदेशनीति आजादी के शुरुआती दौर में उपनिवेशवादी विचारधारा, महात्मा गांधी के नैतिक विचार, गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नीतियाँ, अरब राज्यों का समर्थन, आंतरिक और सामरिक हित आदि से प्रभावित थी उस दौरान भारत ने 1950 में आधिकारिक तौर पर इजराइल को राज्य के रूप में मान्यता दे दिया लेकिन पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित नहीं किए फिर भी इजराइल ने रक्षा क्षेत्र, खुफिया जानकारी साझा करने और कृषि के क्षेत्र में सीमित लेकिन महत्वपूर्ण सहायता की 1962 के भारत चीन युद्ध और 1965 व 1971 के भारत पाक युद्ध में इजराइल भारत को चुपचाप तथा अप्रकाशित रूप से सैन्य उपकरण व गोला बारूद प्रदान किया। पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद से निपटने के लिए इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने भारत को खुफिया जानकारी प्रदान करने में सहायता की साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत जोकि फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा लेकिन इजराइल कूटनीतिक रूप से जवाबी कार्यवाही करने से परहेज किया।

1990 से 2014 तक इजराइल और फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत के दृष्टिकोण

जैसा कि उपर्युक्त विश्लेषण से पता चला कि भारत लगातार हर मुद्दे पर फिलिस्तीन और अरब देशों का समर्थन किया लेकिन 1990 के बाद कई भू–राजनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक परिवर्तन हुए जिसकी वजह भारत के दृष्टिकोण बहुआयामी, व्यवहारिक, हित आधारित और बहु–संरेखण होती चली गई इसके पीछे भी कई कारक जिम्मेदार है –

कारण –

1. शीत युद्ध की समाप्ति के बाद एक नई विश्व व्यवस्था का आगाज हुआ जिसमें रूस का पतन और अमेरिका का एक महाशक्ति के रूप में उभार, इस नई वैश्विक प्रणाली में भारत रूस जैसे एक महत्वपूर्ण राजनयिक और सैन्य साझेदार खो दिया ऐसी परिस्थिति में भारत को अमेरिका के साथ संबंध स्थापित करने तथा अपने कूटनीतिक संबंधों में विविधता लाने और इजराइल के साथ कृषि, सूचना संचार तकनीक व सैन्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में कूटनीतिक सहयोग बढ़ाने के लिए आगे बढ़ा, साथ ही 1990 के दशक में आई आर्थिक मंदी ने भारत को पश्चिमी देशों के साथ संबंध मजबूत करने के लिए एक अवसर प्रदान किया।
2. फिलिस्तीन मुद्दा जो वर्षों से वैश्विक उपनिवेश विरोधी और गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रमुख भाग था अब वह शांति की ओर बढ़ने लगा जैसे 1991 में मैड्रिड सम्मेलन और 1993 में ओस्लो समझौता। यह समझौता भारत को बिना किसी दबाव व अरब प्रतिक्रिया के इजराइल के साथ सहयोगात्मक संबंध बनाने का मौका प्रदान किया एक अन्य समस्या पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीय–करण कर अरब देशों का सहयोग पाने के निरंतर प्रयास में कमी आने लगी थी क्योंकि अरब देशों में कई इस्लामिक आंदोलन का पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने पर उसकी विश्वसनीयता कम हो गई थी जिसकी वजह से भारत को अरब देशों का कश्मीर मुद्दे पर समर्थन ना मिलने का डर खत्म हो गया इस घटनाक्रमों ने भी भारत को इजराइल के साथ संबंधों मजबूत करने का अवसर प्रदान किया।
3. 1980 के बाद कश्मीर में लगातार बढ़ते आतंकवादी घटनाओं से निपटने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी और खुफिया जानकारी और आतंकवाद विरोधी विशेषज्ञता की आवश्यकता पड़ी जिसमें इजराइल एक महत्वपूर्ण सहयोगी बनकर उभरा।
4. रूस के पतन के बाद चीन की बढ़ती ताकत को प्रति–संतुलित करने के लिए भारत को अमेरिका के साथ संबंधों को मजबूत करना आवश्यकता बन गई। इजराइल जोकि अमेरिका का सबसे करीबी सहयोगी है, ऐसे में इजराइल के साथ भारत के बढ़ते मधुर संबंध अमेरिका के साथ जुड़ने में मदद करेगा और भारत को रक्षा, प्रौद्योगिकी और आतंकवाद–रोधी जैसी समस्या से निपटने में भी मदद करेगा।
5. 1990 के दशक में भारत की विदेशनीति अधिक व्यवहारिक और कम विचारधारा आधारित होती जा रही थी जिसमें राष्ट्रीय हित को अधिक प्राथमिकता देते हुए भारत फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने पारंपरिक समर्थन को इजराइल के साथ बढ़ते सामरिक और आर्थिक संबंधों के साथ संतुलित करने का प्रयास किया अर्थात वह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिलिस्तीन का समर्थन जारी रखा लेकिन इजराइल के प्रति कठोर रुख अपनाने से बचाव करने लगा।

1992 में इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हुए संघर्ष को लेकर भारत का दृष्टिकोण विचारधारा–संचालित से व्यवहारिक हित आधारित हो गई भारत दो राष्ट्र सिद्धांत का समर्थन करते हुए संतुलनकारी विचारधारा अपनाया इस परिवर्तित दृष्टिकोण को 1990 के बाद इजराइल फिलिस्तीन के मध्य हुए संघर्षों को लेकर भारत द्वारा दिए गए बयानबाजी में देखा जा सकता है।

1990 का दशक – इस दशक में अरब इजराइल देशों के मध्य कई शांति समझौता हुआ जैसे 1991 का मैड्रिड सम्मेलन जो अरब देशों में शांति स्थापित करने का एक असफल प्रयास रहा लेकिन यह सम्मेलन भविष्य के वार्ता के लिए एक आधार तैयार कर दिया इसी दिशा में अगला समझौता– ओस्लो समझौता यह इजराइल और फिलिस्तीन मुक्ति संगठन के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसमें इजराइल पश्चिमी तट और गाजा से अपनी सेना वापस बुलाएगा जिस पर फिलिस्तीन प्राधिकरण को सुरक्षा कार्यों तथा प्रशासनिक नियंत्रण का अधिकार होने से सीमित स्वशासन का अधिकार मिल जाएगा इस समझौते को और विस्तार देने हेतु ओस्लो समझौता द्वितीय 1995 में हुआ। एक अन्य समझौता 1994 में इजराइल और जार्डन के बीच हुआ जार्डन मिश्र के बाद दूसरा अरब देश बना जिसने इजराइल राज्य को औपचारिक मान्यता दी। उपर्युक्त शांति सम्मेलन का सकारात्मक परिणाम भारत और इजराइल के संबंधों पर पड़ा 1992 में भारत इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित किया साथ ही अरब देशों की प्रतिक्रिया का सामना और फिलिस्तीन को लेकर वर्षों से चले आ रहे सहयोगात्मक दृष्टिकोण में व्यापक परिवर्तन किए बिना इजराइल के साथ रक्षा, खुफिया, और व्यापार संबंधों को मजबूत करने का अवसर मिला। लेकिन यह शांति बहाल ज्यादा समय तक नहीं रहा क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के उग्रवादी गुट ने येरूशलम, शरणार्थियों और अंतिम सीमाओं जैसे मुद्दे को लेकर आपसी अविश्वास को बढ़ावा दिया इजराइल ने पश्चिमी तट और पूर्वी येरूशलम में यहूदी बस्तियों के विस्तार पर रोक नहीं लगाई जिस कारण फिलिस्तीनी कट्टरपंथी और इस्लामिक जिहाद ओस्लो समझौते को अपने साथ विश्वासघात माना जिसको ध्यान में रखते हुए एक तरफ हमास जैसे कट्टरपंथ इजराइली नागरिकों के खिलाफ आत्मघाती बम विस्फोट और अन्य आतंकवादी हमले शुरू कर दिए वहीं दूसरी तरफ ओस्लो समझौते के वस्तुकार यित्जाक रॉबिन की इजराइली दक्षिणपंथी ने

हत्या कर दी और वहाँ की राजनीतिक माहौल ने बेंजामिन नेतन्याहु को अगला प्रधानमंत्री चुना जो इस समझौते से ज्यादा राष्ट्रीय सुरक्षा व बस्तियों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया। यही मुख्य कारण पुनः इजराइल और फिलिस्तीन को संघर्ष के गर्त में धकेल दिया और द्वितीय इंतिफादा की शुरुआत हो गई।

द्वितीय इंतिफादा (2000–2005) – इजराइल के विपक्षी नेता एरियल शेरोन की अल अक्सा मस्जिद की यात्रा का फिलिस्तिनी द्वारा विरोध किया गया यह बड़े पैमाने पर हिंसा को जन्म दिया इस हिंसा के दौरान भारत फिलिस्तीन के साथ अपनी पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने के साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में इजराइल द्वारा किए गए अत्यधिक बल प्रयोग की आलोचना करने वाले प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया भारत 1967 के पहले 'संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्तुत विभाजन रेखा पर सहमति देते हुए इजराइल के कब्जे वाले फिलिस्तिनी क्षेत्र को स्वतंत्र करने का आवाहन किया और दोनों पक्षों को तत्काल शांति की राह को अपनाने का आग्रह किया इस समर्थन के बावजूद भारत इजराइल के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को दरकिनार नहीं किया यह दिखाता है कि भारत किस तरीके से दोनों पक्षों को लेकर अपना तटस्थ और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखा।

ऑपरेशन कास्ट लीड (2008–2009) (जिसे गाजा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है) जिसका उद्देश्य हमास और फिलिस्तिनी आतंकवादी समूहों द्वारा किए गए रॉकेट फायर को रोकना इसका परिणाम गाजा में व्यापक जान माल की हानि हुई, पर भारत अपने पुराने दृष्टिकोण को दोहरते हुए इजराइल द्वारा किए गए अत्यधिक बल प्रयोग की निंदा तो की लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इजराइल को दोषी ठहरने से परहेज किया साथ ही हमास के द्वारा किए गए कार्यवाही का खुलकर समर्थन नहीं किया **इसी तरह ऑपरेशन पिलर ऑफ डिफेंस 2012** पर भारत ने दोनों पक्षों से युद्ध विराम करने का आग्रह किया साथ ही गाजा में नागरिक हताहतों और विनाश पर चिंता जताया और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता दी।

2014 के बाद इजराइल और फिलिस्तीन को लेकर भारतीय दृष्टिकोण –

देखा जाए तो आजादी से पहले और आजादी के बाद 1990 तक भारत का दृष्टिकोण फिलिस्तीन समर्थक रहा वहीं 1990 के बाद 2014 तक भारत का इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष को लेकर दृष्टिकोण मध्यम मार्गी रही जिसमें भारत फिलिस्तीन के लिए अपने पारंपरिक समर्थन को बनाए रखने के साथ–साथ इजराइल को भी संतुलित करने का प्रयास किया लेकिन 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद, जो लंबे समय से इजराइल के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने सिफारिश कर रही थी, फिलिस्तीन और इजराइल को संतुलित करने वाली पारंपरिक दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया जो इन दोनों पक्षों को अलग–अलग मानकर स्वतंत्र (फिलिस्तीन को संतुलित किए बिना) संबंध बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित किया जिसे डी–हाईफनेशन सिद्धांत कहा गया हालांकि 1999–2004 तक एनडीए की सरकार सत्ता में रही लेकिन वर्षों से चले आ रहे फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण को व्यापक रूप से परिवर्तित नहीं कर पाए इसके पीछे मुख्य कारण दृ अरब जगत पर भारत की ऊर्जा निर्भरता, फिलिस्तीन के प्रति ऐतिहासिक प्रतिबद्धता, भारतीय आ–प्रवासन, अंतर्राष्ट्रीय दबाव व वैश्विक सहमति, घरेलू राजनीतिक बाधाएं (मजबूत विपक्षी दल कांग्रेस जोकि अपनी पहचान काफी हद तक फिलिस्तीन के प्रति समर्थन रूप में बनाई थी), जिम्मेदार थी इसलिए माना जाता है कि फिलिस्तीन से इजराइल की तरफ व्यापक व्यवहारिक दृष्टिकोण में परिवर्तन 2014 के बाद भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलने के साथ शुरुआत हुई। इस परिवर्तन को इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य हुए संघर्षों पर भारत के रुख और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर बयान बाजी के आधार पर देखा जा सकता है।

ऑपरेशन प्रोटेक्टिव एज – 2014 में इजराइल और हमास के मध्य गंभीर संघर्ष हुआ भारत ने इजराइल को आत्मरक्षा के अधिकार को स्वीकार करते हुए हिंसा पर अफसोस जताया लेकिन संसद में इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव लाने से इनकार कर दिया और 2015 में गाजा में इजराइल के "कथित युद्ध अपराधों की आलोचना" करने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हो रहे वोटिंग से परहेज किया यह पहली बार था जब भारत द्वारा फिलिस्तीन के पारंपरिक समर्थन के खिलाफ हटकर एक संतुलनकारी दृष्टिकोण अपनाया।

गाजा सीमा संघर्ष 2018 – फिलिस्तीन द्वारा इजराइल की सीमा पर प्रदर्शन किए जाने पर इजराइली सैन्य बलों द्वारा कार्यवाई किए जाने पर अनेक नागरिक घायल हुए इसको लेकर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिद में इजराइल के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया जो इसके सैन्य कार्यवाई की कड़ी निंदा से संबधित थी लेकिन भारत वोटिंग में अनुपस्थित रहकर अपने बदलते दृष्टिकोण का स्पष्ट संकेत दिया इसी तरह "गाजा इजराइल संघर्ष 2021" में भारत ने सभी पक्षों को संयम बरतने व यथास्थिति बनाए रखने की अपील की साथ ही भारत ने फिलिस्तिनियों के अधिकार और इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार के महत्व को स्वीकारा जिससे यह स्पष्ट हुआ कि भारत अब भावनात्मक समर्थन के बजाय रणनीतिक समीकरणों को प्राथमिकता दे रहा है। 2017 में जब अमेरिका द्वारा येरूशलम को इजराइल की राजधानी घोषित किया गया तब भारत संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के पक्ष में

वोट देकर संतुलनकारी दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया। 2019 में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद में एक प्रस्ताव 'जिसमें फिलिस्तीनी गैर सरकारी संगठन "Shahed" को यूएनओ में विशेष परामर्शी' दर्जा देना शामिल था जिसपर इजराइल आतंकवादी गतिविधियों व चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, भारत इजराइल के पक्ष में वोट देकर Shahed का विरोध किया यह इजराइल के प्रति भारत का पहला स्पष्ट समर्थन माना गया इस मतदान ने यह संकेत दिया कि भारत अब संयुक्त राष्ट्र में अपने पारंपरिक मतों के बजाय मुद्दों की प्रकृति, संगठन की वैधता और राष्ट्रीय हित के आधार पर निर्णय ले रहा है इससे पहले भारत अधिकतर ऐसे प्रस्ताव में अनुपस्थित या तटस्थ रुख अपनाता रहा।

हमास इजराइल युद्ध 2023 – 7 अक्तूबर 2023 को हमास द्वारा इजराइल पर हमला किया गया जिसमें 1300 से अधिक हत्या और सैकड़ों बंधक बना लिए गए उसके बाद इजराइल और हमास द्वारा एक दूसरे लगातार सैन्य कार्यवाई की गई यह संघर्ष पूरे मध्य पूर्व में अस्थिरता को जन्म दिया इजराइल लगातार आतंक के खिलाफ सैन्य कार्यवाई को अंजाम दे रहा है यह संघर्ष आज भी (2025) पूरे मध्य पूर्व में बना हुआ भारत ने हमास द्वारा किए गए हमले की कड़ी निंदा की और इसे आतंकवाद का अमानवीय चेहरा बताया तथा इजराइल के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए एकजुटता प्रकट की 8 अक्तूबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री ट्वीट करके कहा कि "हम हमास द्वारा इजराइल पर किए गए आतंकवादी हमले की निंदा करते है और भारत इस कठिन परिस्थिति में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े है" यह पहला अवसर था जब भारत ने इजराइल के समर्थन में ऐसे बयान देने के बाद तुरंत कोई संतुलित बयान नहीं दिया **(जंनतुल नईम पियाल, दी डिप्लमैट)** अक्तूबर 2023 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में युद्ध विराम और मानवीय सहायता से संबंधित प्रस्ताव पर भारत मतदान से दूरी बनाकर यह संदेश दिया कि 'जब तक प्रस्ताव में आतंकवाद की निंदा नहीं की जाएगी तब तक भारत इस प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकता' क्योंकि भारत भी लगातार आतंकवाद की मार झेल रहा है और मौजूदा संघर्ष को आतंकवादी–रोधी दृष्टिकोण से देखा और ऐसे आतंकवादी रोधी अभियान मानवीय संघर्ष विराम के लिए नहीं रुकते। **(जंनतुल नईम पियाल दी डिप्लमैट)** भारत राष्ट्रीय हित को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र में "गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव" पर तीन साल में चौथी बार अनुपस्थित रहकर और एक प्रस्ताव पर मतदान न करके मोदी सरकार इजराइल के प्रति प्रत्यक्ष समर्थन दिखाया **(सुधा रामचंद्रन, दी डिप्लमैट)** हालांकि जैसे–जैसे गाजा पट्टी में मानवीय संकट बढ़ा भारत संतुलनकारी नीति अपनाते हुए फिलिस्तिनी नागरिकों को मानवीय सहायता देने के साथ– साथ दोनों देशों को संघर्ष में संयम बरतने व अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने का आग्रह किया।

कारण – 2014 के बाद फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण में परिवर्तन रणनीतिक यथार्थवाद, राष्ट्रीय हित रक्षा सहयोग और वैश्विक शक्ति संतुलन के कारण हुआ है हालांकि भारत अब भी फिलिस्तीन की "द्वि–राष्ट्र समाधान" नीति का समर्थन कर रहा है लेकिन अब उसकी प्राथमिकता रणनीतिक साझेदारियों की ओर स्पष्ट रूप से स्थानांतरित हो चुकी है। **इसके पीछे भारत कई कारण मौजूद है–**

डीहाईफनैशन की नीति – डी–हाईफनेशन का शाब्दिक अर्थ हाइफन (–) हटना विदेशनीति में इसका अर्थ है किसी दो देशों के साथ भारत के संबंधों को एक–दूसरे से जोड़कर न देखना बल्कि दोनों के साथ स्वतंत्र और समानांतर रूप से संबद्ध विकसित करना इस नीति का औपचारिक उपयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में शुरू की गई जिसका तात्पर्य इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष को दो अलग–अलग मुद्दे के रूप में देखना और एक दूसरे के साथ संबंधों प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से अपनी विदेशनीति को संचालित करना जिससे ऐतिहासिक रूप से फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण और इजराइल के साथ विकसित हो रहे द्विपक्षीय संबंध के बीच टकराव ना हो। 2014 से पहले भारत hyphenated approach अपनाई जिसका तात्पर्य भारत इजराइल और फिलिस्तीन संबंधों को एक दूसरे से जोड़कर देखना अर्थात यदि भारत इजराइल के साथ को संबंध बनाता था तो फिलिस्तीन को संतुलित करना होता था लेकिन 2014 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई तो इस दृष्टिकोण में बदलाव देखा गया डी–हाइफनैशन नीति की स्पष्ट पहचान तब हुई जब भारत के किसी पहले प्रधानमंत्री द्वारा 2017 में इजराइल की ऐतिहासिक यात्रा की गई और जियोनिज्म के संस्थापक थियोडोर हर्जल के कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर जियोनिज्म को मान्यता दी इस यात्रा के परिणाम स्वरूप भारत और इजराइल के मध्य अंतरिक्ष, जल प्रबंधन, कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के लिए कई समझौते हुए इससे यह स्पष्ट हो गया कि भारत अब इजराइल के साथ विकसित हो रहे द्विपक्षीय संबंधों को गुप्त नहीं रखेगा इससे पहले 2014 में भारतीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह इजराइल की यात्रा किया जिसमें फिलिस्तीन को शामिल नहीं किया फिलिस्तीन की अलग से 2018 में इजराइल के दिल्ली यात्रा के ठीक एक महीने बाद किया जिसमें रामल्लाह को 50 मिलियन डॉलर की सहायता की घोषणा की इसका उद्देश्य फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र के रूप में समर्थन देना, भारत 2014 के बाद से संयुक्त राष्ट्र जैसे विभिन्न मंचों पर दो राष्ट्र समाधान, विभिन्न संघर्षों में संयम बरतने की अपील और वार्ता के माध्यम से समाधान जैसे नीतियों का पालन करने का आवाहन किया

2017 में अमेरिका द्वारा येरूशलम को इजराइल की राजधानी घोषित किए जाने पर भारत ने विरोध व निंदा की और इस कदम की निंदा करने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया जो यह दर्शाता है कि भारत अपने समकालीन राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखता इसके लिए वह आज भी फिलिस्तीन समर्थक दृ ष्टिकोण को भी स्थान दे रहा है भले यह समर्थन प्रतीकात्मक व सहयोगात्मक रूप धारण कर ली है क्योंकि इतिहास में फिलिस्तीन समर्थक रुख अपनाने से भारत को बहुत कम लाभ हुआ है उदाहरण स्वरूप कश्मीर मुद्दे पर अरब देश भारत पक्षपाती रुख अपनाने से कतराते रहे इसलिए 2014 के बाद भारत की विदेशनीति पूरी तरह से व्यवहारिक दृष्टिकोण पर आधारित हो चुकी है वर्तमान भारत अपने राष्ट्रीय हितों, नागरिक हितों को प्राथमिकता देते हुए विश्व में खुद एक उभरती हुई शक्ति और एक उत्तरदायी राष्ट्र के रूप प्रस्तुत किया।

वैचारिक संरेखण – वर्तमान भारत और इजराइल के मध्य संबंध उनकी रणनीतिक समानता और साझा वैचारिक आधारों के कारण मजबूत हुआ। भारत जियोनिज्म और हिन्दुत्ववादी दर्शन में समानता प्रदर्शित करता है हिंदुत्ववादी दर्शन से प्रभावित भाजपा सरकार इजराइल को ऐसे मॉडल राष्ट्र के रूप में देखता है जो चारों तरफ शत्रु देश में पनपे आतंकवाद से घिरे रहने के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा हुआ इसके लिए राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण तत्व जिसके लिए वह मजबूत सुरक्षा तंत्र, खुफिया जानकारी रखने और सख्त सैन्य रुख अपनाया है भारत को इससे सबक लेने की जरूरत है क्योंकि यह भी आतंकवाद की समस्या से जूझ रहा है भारत अपने इतिहास में देखता है कि पाकिस्तान द्वारा समर्थित आतंकवाद ने 2001 में संसद पर, 2008 के मुंबई हमला उस समय के इजराइल पर हुए यहूदी चबाड हमला के समान था जिसका इजराइल ने मुह तोड़ जवाब दिया भारत भी यह मानने लगा है कि उसके के पास भी आतंकवाद के कारनामे का जवाब देने की मजबूत इच्छा शक्ति है 2016 में उरी हमला, 2019 में पठानकोट हमला और 2025 में पहलगाम हमले का भारत ने मुहतोड़ जवाब दिया इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हित को पाकिस्तान को संतुलित करने के लिए अरब देशों को और घरेलू राजनीति में वोट बैंक की राजनीति को प्राथमिकता नहीं दे सकता क्योंकि अरब देशों के पास भारत को देने के लिए सीमित संसाधन है जबकि इजराइल के महत्वाकांक्षा, उन्नत तकनीक और गतिशील मुक्त अर्थव्यवस्था से भारत लाभ उठा सकता है।

रणनीतिक और रक्षा हित – भारत और इजराइल के मध्य सुरक्षा सहयोग वर्षों से चले आ रहे है 1962 में इंडिया चीन युद्ध, 1965 एवं 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में इजराइली हथियारों का खुलकर प्रयोग किया लेकिन भारत खुलकर कभी समाने नहीं आया 2014 के बाद भारत इजराइल के सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया जबकि इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता भारत इजराइल के साथ उच्च रक्षा तकनीक बराक–8 मिसाइल, हेरोन, स्पाइक एंटी–टैंक गाइडेड मिसाइल और ड्रोन आदि का सौदा किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए इजराइली रक्षा उपकरण निर्माण कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है उदाहरण स्वरूप राफेल और कल्याणी ग्रुप के बीच संयुक्त उद्यम की स्थापना। इन सैन्य क्षेत्रों में फिलिस्तीन भारत की कभी सहायता नहीं कर सकता इसलिए भारत अपने सीमा सुरक्षा के लिए इजराइल के साथ लगातार संबंधों को मजबूत करने में लगा हुआ है क्योंकि इजराइल भारत को उन्नत प्रकार के हथियार देने के लिए आश्वस्त है बिना यह उम्मीद किए कि वह संयुक्त राष्ट्र में इजराइल का पक्ष लेगा या फिलिस्तीन का।

कृषि और जल संसाधन प्रौद्योगिकी – इजराइल जोकि अत्यधिक शुष्क और जल की कमी वाले क्षेत्र में स्थित है, इजराइल उन्नत तकनीकों और स्मार्ट समाधानों के माध्यम से कृषि और जल प्रबंधन करने में ख्याति प्राप्त की है भारत को जलवायु परिवर्तन के कारण सुख, बाढ़ और अनियमित वर्षा की मार झेलनी पड़ती है ऐसे में भारत इजराइल से ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, जैसे तकनीक की सहायता ले सकता है।

फिलिस्तीन की आंतरिक संकट और नेतृत्वहीनता – भारत और फिलिस्तीन के ऐतिहासिक संबंध स्वतंत्रता संग्राम और गुटनिरपेक्षता की भावना से जुड़े रहे लेकिन 2007 के बाद से लगातार फिलिस्तीन गंभीर राजनीतिक विभाजन से जूझ रहा है हमास गाजा पट्टी पर और फतह वेस्ट बैंक पर कब्जा अपने–अपने तरीके से शासन का संचालन कर रहे है ऐसे में भारत को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वह फिलिस्तीन के किस प्राधिकरण को समर्थन दे फिलिस्तीन की नेतृत्वहीनता, राजनीतिक विभाजन और चरमपंथी संगठनों का प्रभाव भारत जैसे लोकतान्त्रिक, बहुलवादी और स्थिर प्रिय देश के लिए एक गंभीर चुनौती है एक समय था जब फिलिस्तीन को इस्लामिक देशों का भारी समर्थन प्राप्त था लेकिन अब स्वयं इस्लामिक देश इजराइल के साथ शांति समझौता कर कूटनीतिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहे है भारत खुद ये बात समझने लगा है की फिलिस्तीन हमारे देश को न तो ऊर्जा सुरक्षा या तकनीकी सहायता दे सकता और न ही पश्चिमी एशियाई रणनीति में कोई रणनीतिक लाभ, इसलिए भारत फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को सांस्कृतिक और मानवीय सहायता तक सीमित कर दिया अब भारत

की प्राथमिकता आदर्शवाद से अधिक यथार्थवाद, भावनाओं से अधिक रणनीतिक और नैतिकता से अधिक राष्ट्रीय हित हो गई है।

खाड़ी देशों के साथ संतुलन – भारत और इजराइल के बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों के बीच भारत फिलिस्तीन के साथ मानवीय सहायता और सहानुभूति और मध्य एशिया के साथ वर्षों से चले आ रहे तेल और ऊर्जा व्यापार को दरकिनार नहीं किया गया बल्कि विभिन्न कूटनीतिक साधनों के माध्यम से भारत मध्य–पूर्व के साथ आर्थिक, रणनीतिक निवेश, तकनीकी साझेदार और रक्षा संबंधों को नया आयाम दे रहा है भारत को ऐक्ट वेस्ट पॉलिसी ने मध्य पूर्व में एक विश्वसनीय, स्वतंत्र और संतुलित शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो इजराइल, अरब और ईरान जैसे परस्पर विरोधी गुटों से भी संबंध बनाए रखने में मदद करती है क्योंकि अब खुद खाड़ी देश इजराइल के साथ अच्छे संबद्ध बनाने की कोशिश कर रहे है यूएई, बहरीन जैसे देश अब्राहम समझौते (2020) के तहत इजराइल को मान्यता दे चुके है इससे भारत को अब 'सबसे मित्रता' की नीति अपनाने में कोई रुकावट पैदा नहीं हो रही है फिलिस्तीन 2015 में भारत के राष्ट्रपति इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन का दौरा किया यह पहली बार था जब किसी राष्ट्रपति द्वारा इजराइल का दौरा किया गया जिसमें फिलिस्तीन और जार्डन को भी सम्मिलित कर एक संतुलनकारी दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया यह यात्रा रक्षा शिक्षा और तकनीक के क्षेत्र में बहुपक्षीय संबंध बनाने में एक नया आयाम प्रस्तुत किया 2022 में I2U2 समूह की स्थापना और 2023 के जी20 शिखर सम्मेलन में चीन के वन बेल्ट वन रोड पहल का सामना करने के लिए भारत–मध्य पूर्व– यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC) भारत के ऐक्ट वेस्ट पॉलिसी और बहुपक्षीय कूटनीति का प्रमुख उदाहरण है I2U2 चार देशों– भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका के बीच एक ऐसा मंच है जो आर्थिक सहयोग, तकनीकी नवाचार, खाद्य एवं जल सुरक्षा और बुनियादी ढांचों के विकास पर केंद्रित है। 2023 में India-Middle East Europe corridor (IMEC) परियोजना की शुरुआत जिसमें भारत यूएई, सऊदी अरब, यूरोप और अमेरिका शामिल है यह बहुद्देश्यीय परियोजना रेल बंदरगाह, ऊर्जा पाइपलाइन और डिजिटल संपर्क पर आधारित है जो भारत के निर्यातकों के लिए समय और लागत की बचत करेगी है और ऊर्जा परिवहन को सुगम बनाएगी इसी तरह भारत मध्य पूर्व के एक–एक देशों के साथ द्विपक्षीय संबंधों को महत्व दिया भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच 2022 में व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता हुआ और डिजिटल भुगतान प्रणाली (रुपे कार्ड, यूपीआई) को यूएई में क्रियान्वित किया जिससे भारतीय रुपये को अन्तर्राष्ट्रीय–करण करने में मदद मिली। संयुक्त अरब अमीरात अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा वाणिज्यिक भागीदार, दूसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य एर प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का चौथा बड़ा श्रोत है 2016 में सऊदी अरब के साथ भारत ने रणनीतिक साझेदारी स्थापित की और 2019 में स्ट्रेटजिक पार्टनर काउंसिल की स्थापना की 2023 में दोनों देशों ने ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनकरणीय ऊर्जा, स्मार्ट सिटी, पर्यटन, स्वास्थ्य और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में संयुक्त परियोजनाओं की संभावनाओं पर सहमति बनी और "सऊदी विजन 2030" से तालमेल बनाया, ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह परियोजना जोकि भारत के लिए मध्य एशिया और अफगानिस्तान तक पहुँच का वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है जिसको लेकर 2016 में त्रिपक्षीय समझौते के अंतर्गत भारत ने बंदरगाह के विकास में सहायता दी हालांकि अमेरिका प्रतिबंधों ने इस बंदरगाह के प्रगति को प्रभावित किया, फिर भी भारत ने इसके रणनीतिक प्राथमिकता को बनाए रखा 2024 में भारत और ईरान के बीच एक दीर्घ कालिक 10 वर्षीय अनुबंध पर हस्ताक्षर हुए जिसमें भारत को बंदरगाह के संचालन में स्थायित्व और व्यापारिक मार्गों पर नियंत्रण मिला। भारत ने कतर की यात्रा करके द्विपक्षीय सहयोग को और विस्तार व गहरा करने का वादा किया कतर और भारत के बीच 2004 में हुए एलएनजी आपूर्ति अनुबंधों को 2024 में पुनः समझौता जिसमें कतर एनर्जी भारत को दीर्घकालिक और किफायती दरों पर 20 वर्षों तक प्रति वर्ष 7.5 मिलियन मीट्रिक टन एलएनजी की आपूर्ति करने का वादा किया। 2023 में कतर में आठ भारतीयों को मौत की सजा सुनाई गई थी लेकिन कतर की भारत यात्रा और बढ़ते मधुर संबंधों ने 2024 में इन भारतीयों को रिहा कराने में मदद की इसी तरह भारत अन्य मध्य पूर्व देशों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में मधुर संबंध स्थापित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है जिससे देश के राष्ट्रीय हित को सुरक्षा प्रदान की जा सके।

भारत की वैश्विक भूमिका में परिवर्तन – भारत अब नैतिकवादी दृष्टिकोण के बजाय राष्ट्रीय प्रधान और गुटनिरपेक्षता के बजाय बहु–संरेखण की नीति को अपना रहा है वह केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है 2023 में भारत ने जी20 की अध्यक्षता और ग्लोबल साउथ सम्मेलन का आयोजन कर विकासशील देशों की आवाज को प्रमुख मंचों पर प्रस्तुत किया। जी20 सम्मेलन में विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री के कहा कि "पश्चिम एशियाई क्षेत्रों में असुरक्षा और अस्थिरता का माहौल हम सब के लिए चिंता का विषय है हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि इजराइल हमास युद्ध किसी तरह का क्षेत्रीय संघर्ष न बने" **(अनुकृति सिंह)** यदि भारत को अपने विचार को प्रमुखता से विश्व मंच पर मजबूत करना है तो पश्चिमी राष्ट्रों, अमेरिका फ्रांस, इजराइल जापान आदि देशों के साथ घनिष्ठ संबंधों की आवश्यकता होगी ऐसे में भारत उन विषयों से दूर

रहने की नीति अपना रहा है जो इन रणनीतिक भागीदारी के विरुद्ध जा रहा है जैसे फिलिस्तीन समर्थन की परंपरा।

इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सक्रिय भूमिका – भारत अब केवल दक्षिण एशिया तक सीमित नहीं बल्कि वह इंडो पैसिफिक क्षेत्र में एक समुद्री शक्ति के रूप में उभर रहा है दक्षिणी चीन सागर में चीन की आक्रामकता को जवाब देने के लिए वह क्वाड जैसे मंचों पर भारत सक्रिय भूमिका निभा रहा है क्योंकि भारत के लिए सुरक्षा, रणनीतिक संरेखण और भू–राजनीतिक स्थिरता प्राथमिक जबकि फिलिस्तीन समर्थक दृष्टिकोण गौण हो चुकी है क्योंकि फिलिस्तीन न तो भारत के सामरिक स्थिति को मजबूत करते है और न ही रणनीतिक अवसर प्रदान करते है।

भारत की आर्थिक नीति – अर्थव्यवस्था को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए वैश्विक पूंजी को आकर्षित करना, आपूर्ति शृंखला में स्थान बनाना उच्च तकनीकी साझेदारी प्राप्त करना भारत का लक्ष्य बन चुका है इस दिशा में अमेरिका इजराइल और युरोपियन देशों के साथ अतिआवश्यक है ऐसे में भारत फिलिस्तीन के ऐतिहासिक समर्थन के प्रति आक्रामक रुख अपनाने से भारी नुकसान हो सकता है।

निष्कर्ष – भारत राष्ट्रीय हित के अनुसार समय–समय पर अपने विदेशनीति और कूटनीति में परिवर्तन करता रहता है भारत अब एक संप्रभु, व्यवहारिक और सशक्त राष्ट्र के रूप में अपने विदेशनीति को केवल इतिहास या भावनाओं के आधार पर नहीं बल्कि वर्तमान और भविष्य के रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी हितों को केंद्र में रखकर तय कर रहा है आजादी के शुरुआती के कुछ दशकों तक भारत खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन किया क्योंकि उस दौरान भारत उपनिवेशवादी विरोधी, नैतिक आदर्शवाद और गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भावना से प्रेरित था लेकिन अब परिस्थितियाँ बदल चुकी है। वर्तमान समय में भारत के समाने एक अत्यंत जटिल परिस्थिति उत्पन्न हो गई जहां उसे रणनीतिक लाभ और नैतिक साख के बीच संतुलन बनाना पड़ रहा इजराइल के साथ बढ़ते सुरक्षा, तकनीकी और कुटनीतिक संबंध के बीच फिलिस्तीन के साथ ऐतिहासिक समर्थन और मानवीय सहानुभूति संबंधों को सतर्कता पूर्ण भूमिका निभा रहा है उदाहरणस्वरूप अक्तूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइलियों पर हमला किए जाने के बाद भारत उसकी कड़ी निंदा की परंतु साथ ही गाजा में बढ़ते मानवाधिकार संकट पर सहानुभूति दिखाते हुए मानवीय सहायता, दो राष्ट्र समाधान की आवश्यकता पर बल और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानूनों का पालन करने का आवाहन किया। भारत आतंकवाद विरोधी है किसी देश विशेष का नहीं इसलिए उसका इजराइल समर्थक रुख आतंकवाद की अस्वीकृति पर आधारित है, भारत के ऐसा दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि वह विश्व में एक जिम्मेदार राष्ट्र के रूप में शांति, स्थिरता कानून के शासन और क्षेत्रीय संप्रभुता के सम्मान पर जोर देता है। भारत न सिर्फ इस कठिन परिस्थिति में अरब देशों के साथ बल्कि यूरोपीय देश व अमेरिका के साथ भी लगातार संपर्क बनाए रखा हुआ है ताकि विश्व में शांति को बनाए रखा जा सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. एम्ब्रोज, तेजस्विनी, डॉ. (2024), अन्डर्सटैन्डिंग इंडियास स्टैन्ड ऑन इजराइल–पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्टः अन ओवर्व्यू, सोशल विजन, वॉल्यूम 11, इशू 3, पेज 77–86, आईएसएसएन 2349–0519
2. राव, प्रभाकर, बी, डॉ. (2024), इंडियास बैलेसींग ऐक्ट इन इजराइल–पैलेस्टाइन वार, इंटरनेशनल जर्नल मल्टीडिसप्लनेरी एजुकेशनल रिसर्च, वॉल्यूम 13, इशू 7, आईएसएसएन 2277–7881
3. मोटवानी, निशंक. (2023), चेंज एण्ड कान्टिनूइटी इन इंडियास रीलेशन विद इस्राइल एण्ड पैलेस्टिन https://www.mei.edu/publications/change-and-continuity-indias-relations-israel-and-palestine
4. सिंह, अनुकर्ति, डॉ भाटिया, मधू, माहेश्वरी, आर, के, प्रो. (2025), स्ट्रटीजिक बैलेंसिंग एण्ड जीओपलिटिकल नेरटिवसः इंडियास फॉरेन पॉलिसी इन दी इजराइल पैलेस्टीन कान्फ्लिक्ट, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ रिसर्च पब्लिकैशन एण्ड रिव्यूस, वॉल्यूम 6, इशू 3, आईएसएसएन 2582–7421, पृष्ठ–1007–1018
5. पियाल, नईम, जंनतुल. 2023, इंडिया वन्स वाज अ स्ट्रॉंग एली ऑफ पैलेस्टाइन. ह्वट चेंज, दी डिप्लमैट
6. रामचंद्रन, सुधा. (2025), इंडिया सिंगनल्स रीलक्टन्स टू काल आउट इजराइल अग्रेशन, दी डिप्लमैट
7. पाटे, तन्वी. (2020), री– (मोदी) फीइंग इंडियास इजराइल पॉलिसीः अन एक्स्प्लॉरैशन ऑफ प्रैक्टिकल जीओपलिटिकल रीज़निंग थ्रू री–रेप्रिजेन्टेशन ऑफ 'इंडिया' 'इजराइल' एण्ड 'वेस्ट एशिया' पोस्ट–2014 जर्नल ऑफ एसियन सिक्युरिटी एण्ड इंटरनेशनल अफेयर्स (सेज पब्लिकैशन), वॉल्यूम 7, इशू 1, पेज 7–35
8. कौर, विनय. (2017), दी मोदी गवर्नमेंटस पॉलिसी ऑन इजराइलः दी रेट्रोरिक एण्ड रीऐलिटी ऑफ डी–हाइफनैशन, वॉल्यूम 19, इशू 4

9. डार, अहमद, जाहूर. (2024), इंडियास डीपनिंग लव अफेर विद इजराइलः न्यू आस्पेक्टस ऑफ क्वॉपरैशन, जर्नल ऑफ पॉलिटी एण्ड सोसाइटी, 16 (2), 51–62
10. फारुक, जारा. (2025), इंडिया, इजराइल एण्ड दी पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल, https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/complex-emergencies-and-humanitarian-crises/india-israel-and-the-politics-of-control/
11. डे, अनीश, गुप्ता दीक्षा. (2024), एक्सपलोरींग इंडियास अप्रोच टू दी मिडल ईस्ट, इंटरनेशनल पॉलिसी डिजेस्ट, आईएसएसएन 2332–9416
12. गुप्ता, कुमार, अनूप. (2019) इंडियन स्ट्रटीजिक थिंकिंग टूवर्ड्स इजराइलः ए फ्यूचरिस्टिक अप्रोच, वॉल्यूम 7, इशू 1
13. शर्मा, अशोक, एण्ड बिंग, डोव. (2015), इंडिया–इजराइल रीलैशनः दी एवोलविंग पार्टनर्शिप, इजराइल अफेयर्स, वॉल्यूम 21, इशू 4, आईएसएसएन 1353–7121
14. निकोलस, ब्लरेल. (2021), मोदी लूक्स वेस्ट? असससिंग चेंज एण्ड कान्टिनूइटी इन इंडियास मिडल ईस्ट पॉलिसी सिन्स 2014
15. अब्बास, अली, बशीर. (मार्च 2024), अनैलिसिस ऑफ इंडियास वोटिंग पैटर्नस ऑन इजराइल पैलेस्टाइन इसुएस ऐट दी यूनाइटेड नैशन, हिंदुस्तान टाइम्स https://www.hindustantimes.com/analysis/analysis-of-indias-voting-patterns-on-israel-palestine-issues-at-the-united-nations-101710950988836.html
16. दाश, प्रकाश, सत्य. (2024) इजराइल पैलेस्टीन कान्फिलक्टः रोल ऑफ इंडिया एण्ड मेजर ग्लोबल प्लेयर्स, दी जर्नल ऑफ इंडियन एण्ड एशियन स्टडीस, वॉल्यूम 5, नंबर 01
17. अमाल्य, ए. (2024), दी इम्पैक्ट ऑफ ऑन्गोइंग इजराइल–पैलेस्टाइन वॉर ऑन इंडिया नैशनल इन्टरेस्टः बीट्वीन बेनीफिट एण्ड एक्स्पेक्टैशन, जर्नल ऑफ एमेरजिंग टेक्नोलॉगिस एण्ड इन्नोवेटिव रिसर्च, (JETIR. ORG.) वॉल्यूम 11, इशू 12, आईएसएसएन 2349–5162
18- फारुक, जारा. (2025), इंडिया, इजराइल, एण्ड दी पॉलिटिक्स ऑफ कंट्रोल, https://newlinesinstitute.org/state-resilience-fragility/complex-emergencies-and-humanitarian-crises/india-israel-and-the-politics-of-control/